अहमदाबाद से प्रकाशित पाक्षिक R.N.I. No. 54975 /1994
Published on 15th & 30th of Every Month
Permited to post on 3rd & 17th every Month at A'bad PSO under postal Reg. No.
GAMC No. 1488/2017 - 2019 - Valid 2017 up to 31-12-2019

Website - http://www.sindhibandhu.com

सिन्धी बन्धु

गुजरात से सर्वप्रथम प्रकाशित हिन्दी पाक्षिक पत्रिका

We are available at

E-mail: sindhibandhu@yahoo.in

अधिष्ठापक तंत्री - हरिश भागवाणी

E-mail: sindhibandhu@gmail.com

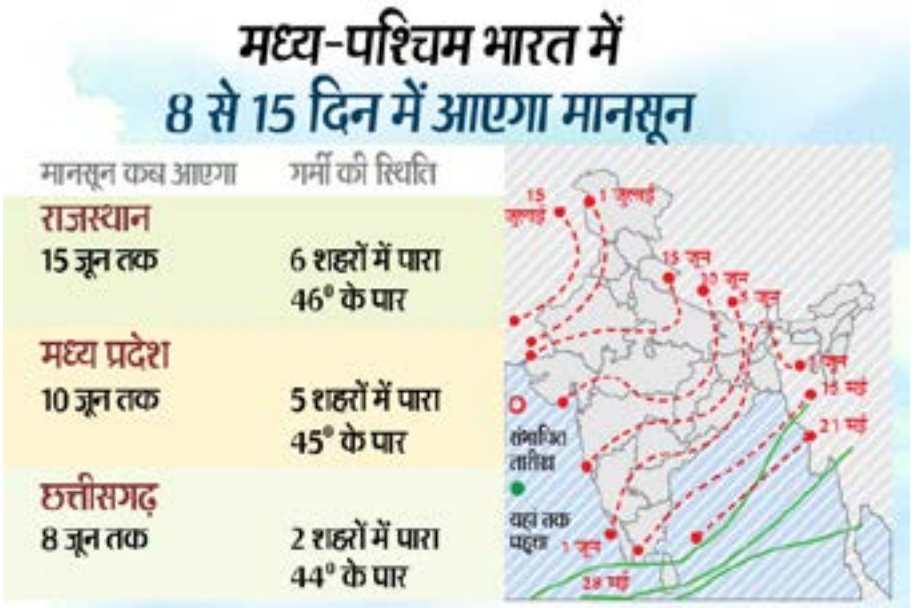

वर्ष *25 अंक 01 * दिनांक 30-05-2018 * संपादक: रेशमा भागवाणी : सहसंपादक - निर्मल भागवाणी : पृष्ठ : 4 * किंमत-1.00 * फोन-22822205 मो.:9429518141

मालिक - मुद्रक -प्रकाशक-संपादक : रेशमा भागवाणी ने लता ग्राफिक्स-२०, सर्जन बंग्लोझ, पार्श्वनाथ टाउनशीप, केनाल के पास, कृष्णनगर, अहमदाबाद से प्रिन्टींग कर के २०, सर्जन बंग्लोझ, पार्श्वनाथ टाउनशीप, केनाल के पास, कृष्णनगर, अहमदाबाद-३८२३४६ से प्रकाशित किया

मौसम विभाग के आखिरी अनुमान में भी सामान्य मानसून की उम्मीद, उत्तर-पश्चिमी भारत में 100% बारिश होगी

मौसम विभाग ने आखिरी पूर्वानुमान में भी लगातार तीसरे साल सामान्य मानसून रहने की बात कही। हालांकि, दक्षिण और उत्तर-पूर्व के राज्यों में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है। मध्य-पश्चिम भारत में मानसून के 8 से 15 दिन में पहुंचने का अनुमान है। देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। दीर्घावधि (लॉन्ग पीरियड एवरेज) में 97 फीसदी मानसूनी बारिश के आसार हैं। बता दें कि 97 से 104 फीसदी के बीच दीर्घावधि की मानसूनी बारिश को सामान्य माना जाता है। इससे पहले अप्रैल में जारी किए गए अनुमान में भी मौसम विभाग ने मानसून सामान्य रहने की बात कही थी।

किन इलाकों में कितने फीसदी बारिश का अनुमान

- मौसम विभाग ने बताया कि देश में मानसूनी बारिश का औसत 97 फीसदी रहने का अनुमान है। जुलाई में दीर्घावधि की 101% और अगस्त में 94% बारिश का अनुमान है।

उत्तर-पश्चिम	100%
मध्य भारत	99%
दक्षिण	95%
उत्तर-पूर्व	93%

मानसून ने केरल कवर किया, कर्नाटक-तमिलनाडु की ओर बढ़ा

- दक्षिण-पश्चिम मानसून इस साल 3 दिन पहले केरल पहुंचा। ये करीब-करीब पूरे केरल को कवर चुका है। मानसून अब कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है।

कर्नाटक के मेंगलोर और उडुपी में रिकॉर्ड, बारिश बाढ़ के हालात

- कर्नाटक के मेंगलोर और उडुपी में 34 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। मेंगलोर के पनामबुर में 33.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों के मुताबिक, पनामबुर में बारिश ने 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उदयनगर में बारिश के दौरान हादसे में एक महिला की मौत की भी खबर है।

रेड अलर्ट जारी:मौसम विभाग के मुताबिक, यह बारिश मेकुन तूफान के असर से हो रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। मेंगलोर और उडुपी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ज्यादातर बाजार बंद हैं।

मोदी ने की अधिकारियों से बात:कर्नाटक में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में बारिश से प्रभावित होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और बेहतरी की कामना करता हूं। अधिकारियों से बात की है और उनसे प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद पहुंचाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव के काम में लगाया है।

10 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट

- मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, प. बंगाल और सिक्किम में आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की हैं।

- जहां एक ओर केरल में मानसून ने तीन दिन पहले ही दस्तक दे दी है। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चार-पांच दिन अभी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। राजस्थान के 6 शहरों में पारा 46 डिग्री के पार है। गंगानगर में पारा 49 डिग्री के करीब पहुंच गया। मध्य प्रदेश का ग्वालियर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। यहां बुधवार को पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया।

अच्छी बारिश, यानी मजबूत इकोनॉमी

मानसून के दौरान देश की 70% बारिश होती है। आधी से अधिक जमीन को इससे फायदा होता है। 80 करोड़ आबादी खेती के लिए मानसून पर निर्भर है। {खरीफ फसल के दौरान आधे से ज्यादा खाद्य पदार्थों की पैदावार होती है। धान, जूट, गन्ना, दालें प्रमुख हैं। महंगाई दर में कमी आती है। ब्याज दरें भी घटती हैं। 2014 में उपभोक्ता मांग 6.2% बढ़ी थी। अच्छी बारिश के बाद 2017 में यह 7.9% तक बढ़ गई।

PNB घोटाला: नीरव मोदी के 7000 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, ED स्पेशल कोर्ट में करेगा अपील

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में फ्रॉड कर भागे नीरव मोदी के 7,000 करोड़ रुपए के एसेट्स की तत्काल जब्ती के लिए मुंबई की स्पेशल कोर्ट में जाने का फैसला किया है। यह जब्ती हाल ही में लागू हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत की जाएगी।

ED नीरव मोदी को भगोड़ा कैटेगरी में रखने के लिए आधिकारिक घोषणा किए जाने की मांग भी करेगा। यह मांग मुंबई के स्पेशल कोर्ट में ED द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत पिछले हफ्ते दायर की गई चार्जशीट के आधार पर की जाएगी।

चार्जशीट में 24 लोगों को बनाया आरोपी

24 मई को ED ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के PNB फ्रॉड केस में पहली चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में ED ने 24 लोगों को आरोपी करार दिया है। इनमें नीरव मोदी समेत उनके पिता, भाई नीशाल मोदी, बहन पूर्वी मोदी, पूर्वी के पति मयंक मेहता और डिजाइनर ज्वैलर्स फर्म मेसर्स सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टैलर डायमंड्स और डायमंड्स R Us शामिल हैं।

ED ने अपनी चार्जशीट में कहा कि नीरव मोदी और अन्य लोगों द्वारा फर्जी कंपनियों के जरिए विदेश में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फंड का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि नीरव मोदी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। साथ ही नीरव मोदी को दुनिया में कहीं भी गिरफ्तार किए जाने को लेकर वारंट जारी करने के लिए ED ने इंटरपोल से भी कॉन्टैक्ट किया है।

सोमवार को इस चार्जशीट पर हो सकती है सुनवाई

एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, कोर्ट द्वारा 12,000 पेजों की इस चार्जशीट पर सोमवार को विचार किए जाने की उम्मीद है। वहीं ED की ओर से काउंसिल नीरव मोदी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधयादेश के प्रावधान अमल में लाने और उनके भारत और विदेश में मौजूद सभी एसेट्स की तत्काल जब्ती की मंजूरी मांगेगी।

मेहुल माल्या के खिलाफ भी होगा एक्शन

ED अपनी दूसरी चार्जशीट दायर करने के बाद नीरव मोदी के मामा और ज्वैलर मेहुल चौकसी और उनके कारोबारों के खिलाफ भी इसी तरह का एक्शन लेगा। बता दें कि PNB फ्रॉड केस में मेहुल चौकसी भी शामिल हैं और इस वक्त नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों देश से बाहर हैं। नीरव मोदी के अलावा ED भगौड़े शराब व्यवसायी विजय माल्या के खिलाफ भी यही कार्रवाई करने वाला है। माल्या के खिलाफ ED और CBI पिछले साल ही चार्जशीट दायर कर चुके हैं।

मौजूदा कानून में केस ट्रायल खत्म होने से पहले नहीं हो सकती जब्ती

ED ने बड़े घोटाले कर देश से बाहर भाग जाने वाले और बैंक लोन डिफॉल्टर्स को नए कानून के तहत नोटिफाई किए जाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। PMLA के कानून के तहत अभी ED केवल तभी एसेट्स की जब्ती कर सकता है, जब किसी केस की सुनवाई पूरी तरह खत्म हो जाए। ऐसा होने में आम तौर पर कई साल लग जाते हैं।

200 करोड़ रु. से ज्यादा के फ्रॉड आएंगे नए अध्यादेश के दायरे में

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश पिछले महीने लाया गया था। नए लागू हुए अध्यादेश का उद्देश्य भारतीय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाने वाले आर्थिक अपराधियों को कानूनी कार्रवाई से बच निकलने से रोकना है।

संपादकीय

मूडीज ने 2018 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 7.3% किया

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2018 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.5% से घटाकर 7.3% कर दिया है। मूडीज ने ग्रोथ अनुमान घटाने की वजह तेल कीमतों को बताया है। हालांकि 2019 के लिए ग्रोथ रेट 7.5% बरकरार रखी है। रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2018-19 के आंकड़ों में ये अपडेट किया है। हालांकि जीडीपी के लिए अनुमान घटाने के बाद भी मूडीज का अनुमान एसबीआई और फिक्की से ज्यादा है।

महंगे तेल का इकोनॉमी पर असर होगा: मूडीज

- मूडीज का मानना है कि भारत की इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है, लेकिन तेल कीमतों में बढ़ोतरी और कमजोर वित्तीय हालातों की वजह से ग्रोथ धीमी होगी।

ग्रामीण अर्थव्यवथा से फायदे की उम्मीद

- मूडीज ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे और सामान्य मॉनसून से ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ेगी जिससे विकास दर को फायदे की उम्मीद है। निजी निवेश में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। रेटिंग एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड से बैंकों और कॉरपोरेट्स की हालत में सुधार होगा।

ग्रोथ पर जीएसटी का असर होगा

- मूडीज के मुताबिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से आने वाले महीनों में ग्रोथ पर नेगेटिव असर हो सकता है। साथ ही कहा है कि एक साल के अंदर ये सभी पहलू सुलझ जाएंगे।

7.5% रहेगी तिमाही जीडीपी ग्रोथ: एसबीआई

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान है कि 2017-18 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ दर 7.5% वहीं पूरे साल के लिए 6.7% रह सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट ईकोरैप में ये अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के ऑथर और एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष के मुताबिक, कॉर्पोरेट ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) के अच्छे प्रदर्शन से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9% रहने की उम्मीद है। साथ ही कहा है कि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ केंद्रीय सांख्यिकी विभाग (सीएसओ) के अनुमान से बेहतर रहेगी। एसबीआई ने सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 8% से ऊपर रहने की उम्मीद जताई है मार्च तिमाही में 7.1% ग्रोथ की उम्मीद: फिक्की सर्वे

उद्योग संगठन फिक्की के सर्वे में 2017-18 की चौथी तिमाही में ग्रोथ रेट 7.1% और पूरे वित्त वर्ष के लिए 6.6% रहने का अनुमान जताया है। फिक्की के इस सर्वे में 2018-19 के लिए आर्थिक विकास दर 6.9% से 7.5% के बीच रहने की बात कही गई है।

अक्टूबर-दिसंबर में 7.2% रही जीडीपी ग्रोथ

केंद्रीय सांख्यिकी विभाग गुरुवार को जनवरी-मार्च तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी करेगा। 2017-18 के अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में जीडीपी दर 7.2% रही थी।

हार्दिक अभिनंदन

श्री रणधीर कुमार - शाखा प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक

हितेश दादवाणी (SBI Home Loan Counsellor)

और परिवार की तरफ से (M. 9979026137 / 7600026137)

पूज्य जुलेलाल साईं थान मंदिर मणीनगर, अहमदाबाद में गायत्री हवन का कार्यक्रम

ता. 27/07/2018 शुक्रवार के दिन
सुबह 11 बजे

प्रवेश निशुल्क

और इसी के साथ पूज्य चालिहा साहब का सुभारम्भ होगा

कार्यक्रम आयोजक
लोकेश आहूजा
M. 9898380180

Ex. MLA मायाबेन कोडनानी के सन्मान मैं20-05 को महावीर कसरत शाला में प्रोग्राम रखा गया

मोदी सरकार ने वेबसाइट पर डाली 4 साल की उपलब्धियां

चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी सरकार ने 48months.mygov.in वेबसाइट तैयार की है। इस पर मई 2014 से लेकर अब तक की सरकार की सभी उपलब्धियों का लेखा-जोखा है। चौथी एनिवर्सरी पर उपलब्धियों के बारे में यह जानकारी लोगों तक पहुंचाने का ये डिजिटल रास्ता है।

वेबसाइट की खासियत है उसके इंफोग्राफिक्स। जबकि उसके परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पर अलग-अलग स्कीम के अचीवमेंट नंबर में बताए गए हैं। इसके मुताबिक 48 महीनों में देश के 3 लाख 71 हजार गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं, जबकि 77 करोड़ घरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनवाए गए हैं। 171393 किमी की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवाई गई हैं और 134,546,471 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा उज्जवला योजना और उजाला स्कीम की डीटेल्स और सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की जानकारी भी वेबसाइट के परफॉर्मेंस डेशबोर्ड पर चिपकाई गई हैं।

वेबसाइट पर सरकार के मंत्रियों के ब्लॉग भी हैं और सरकारी स्कीम का फायदा उठाने वालों के अनुभव भी। विकास, युवाशक्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, किसान जैसे मुद्दों पर सरकार के पक्ष और पहल की जानकारी फोकस एरिया सेक्शन का हिस्सा बनी हैं। हा 48 महीनों को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है और पोस्टर, फोटो, वीडियो डाउनलोड करने के ऑप्शन भी दिए गए हैं। फिलहाल गर्वनेंस क्विज का लिंक काम नहीं कर रहा है और उसका इंतजार हो रहा है। गौरतलब है कि ये वेबसाइट सरकारी की यूटिलिटी वेबसाइट www.mygov.in का ही डोमेन इस्तेमाल कर रही है।

मानसरोवर में स्नान पर कोई रोक नहीं, लेकिन इसकी जगह तय होती है: सुषमा स्वराज

नई दिल्ली.मानसरोवर झील में स्नान करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसकी जगह तय है। सुषमा स्वराज ने यह बात वहां पहुंचे श्रद्धालुओं की शिकायत पर कही है। तीर्थ यात्रियों का आरोप था कि चीनी अफसर उन्हें मानसरोवर झील में नहाने की इजाजत नहीं दे रहे। हालांकि, ये तीर्थयात्री मानसरोवर यात्रा का हिस्सा नहीं हैं। यह यात्रा अगले महीने से शुरू होगी। बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसी महीने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी। इसके बाद चीन ने श्रद्धालुओं के लिए नाथूला दर्रा खोलने की सहमति जताई थी और इसकी जानकारी खुद सुषमा स्वराज ने दी थी।

डोकलाम विवाद के बाद बंद कर दिया गया था नाथूला पास

- पिछले साल जून से अगस्त के बीच करीब 72 दिनों तक चले डोकलाम विवाद के बाद चीन ने कैलाश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नाथूला पास बंद कर दिया था।
- इसके बाद इसी साल मई में सुषमा ने वांग यी से बातचीत की और कहा, "दोनों सरकारों के बीच संबंध तब तक समृद्ध नहीं हो सकते जब तक एक-दूसरे देश के लोगों के बीच रिश्ते मजबूत न हों। पिछली यात्रा के दौरान नाथुला दर्रा बंद कर दिया गया था तो उससे लोगों को बहुत धक्का लगा था।"
- बातचीत के बाद सुषमा ने कहा था- मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब यह खोल दिया गया है। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।

इस साल 1580 श्रद्धालु जाएंगे कैलाश

- विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस साल 1580 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। इनमें से 50-50 श्रद्धालुओं वाले 10 जत्थे नाथुला दर्रा (सिक्किम) और 60- 60 श्रद्धालुओं वाले 18 जत्थे पारंपरिक मार्ग लिपुलेख दर्रे (उत्तराखंड) के रास्ते अपनी यात्रा पूरी करेंगे।
- जून में शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा चार महीने तक चलेगी। इसका ड्रॉ निकलने से पहले श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच की जाती है। 18 साल से अधिक और 70 वर्ष से कम उम्र के श्रद्धालु ही इस यात्रा पर जा सकते हैं।

सिंधी समाज ने प्री-वेडिंग शूट पर बैनः नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना

उज्जैन में सिंधी समाज ने प्री-वेडिंग वीडियो शूट और फोटोग्राफी पर रविवार से प्रतिबंध लगा दिया है. इसका उल्लंघन करने पर वर और वधू पक्ष से 10-10 हजार रु. जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा दोनों पक्षों को समाज के सामने आकर माफी मांगना होगी कि वे आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे. समाज ने दो और फैसले लिए हैं. वह यह कि उठावना अब अंतिम संस्कार के दूसरे दिन सुबह 9.30 बजे होगा. रविवार के दिन सभी कारोबारी छुट्टी रखेंगे और परिवार के साथ वक्त बिताएंगे.

रविवार को हुई अखिल भारत लाढी लोहाणा सिंधी पंचायत नगर इकाई की साधारण सभा में यह फैसले लिए गए. समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि प्री-वेडिंग शूट सामाजिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है. समाज के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि अब तो प्री-वेडिंग शूट के दौरान खींची गई तस्वीरों और वीडियो को शादी के दौरान बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाने लगा है. पति-पत्नी का रिश्ता पवित्र और निजी है. ऐसे में इस तरह की तस्वीरों और वीडियो को प्रदर्शित करना मर्यादा का उल्लंघन है.

मोदी का इंडोनेशिया-सिंगापुर दौरा: चीन पर लगाम कसने की कोशिश, कारोबार-रक्षा के क्षेत्र में भी मदद की उम्मीद

नई दिल्ली.नरेंद्र मोदी 29 मई को सिंगापुर और इंडोनेशिया के 5 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री इस दौरान दोनों देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर करार हो सकते हैं। मोदी का यह इंडोनेशिया का पहला और सिंगापुर का दूसरा दौरा है। मोदी की यात्रा को लेकर दैनिक भास्कर ने विदेश मामलों के जानकार रहीस सिंह से बात की। उनके मुताबिक मोदी के इन दो देशों के दौरे का मकसद जहां एक तरफ चीन पर लगाम कसना है वहीं भारत को कारोबार और रक्षा के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी।

इन वजहों से हो रहा मोदी का दौरा

- रहीस सिंह के मुताबिक, "2015 में सिंगापुर से ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा हुई। 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी का ऐलान हुआ। इसका मतलब था कि पूर्वी देशों की संस्कृति-सभ्यता, सुरक्षा को देखना और उनके करीब जाना। चूंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। लिहाजा हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आ गए ताकि पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से बेहतर संबंध बन सकें"

इंडोनेशिया अहम क्यों?

- "दरअसल चीन का एक न्यू मैरीटाइम सिल्क रूट है, वो इंडोनेशिया के मलक्का से अफ्रीका के जिबूती तक जाता है। यानी एक तरह से ये रूट भारत को घेरता है।

1. भारत इंडोनेशिया से इसी तरह का समझौता करने जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड-डिफेंस गलियारा बनेगा। अगर इंडोनेशिया के साथ हमारा बेहतर तालमेल होता है तो हम चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट को काउंटर कर पाएंगे।

2. चीन पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार-फिलीपींस पर नजर जमाए हुए है। अगर हमारे साथ इंडोनेशिया आ जाता है, तो हम अंडमान-निकोबार के पास चीन के हो रहे जमाव को रोक सकते हैं।

3. इंडोनेशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया में उभरती आर्थिक शक्ति है और मौजूदा वक्त में भारत भी एक वैश्विक ताकत के रूप में सामने आया है। अगर हम इंडोनेशिया के साथ रणनीतिक गठजोड़ बनाते हैं तो चीन से कूटनीतिक सौदेबाजी के वक्त भारत पॉजिटिव साइड में रहेगा।

चीन के सामने चुनौती है सिंगापुर

- "सिंगापुर एक बड़ी मैन्युफेक्चरिंग पावर है। पूर्वी एशिया में अगर चीन के सामने कोई चुनौती है तो वो सिंगापुर है।"

- "चीनी माल के बहिष्कार की बात होती हैं लेकिन भारत डब्ल्यूटीओ नॉर्म के चलते ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ भारत को वो सामान तो मंगाना ही है, फिर वो चाहे चीन से मंगाए या कहीं और से। दूसरी जगह से चीजें मंगाने पर उनकी कीमत ज्यादा हो सकती है। इसका हमारे व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा।"

सिंगापुर से भारत को फायदे

1. सिंगापुर दौरे से भारत के उससे व्यापार संबंध मजबूत होंगे।

2. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ है। ट्रम्प की मौजूदा अस्थिर विदेश नीति के चलते हमें प्रशांत क्षेत्र में अन्य सहयोगियों की जरूरत होगी। अगर भारत सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया को अपने पक्ष में कर लेता है तो भारत मैरीटाइम सिक्युरिटी और ब्लू वॉटर इकोनॉमी को ज्यादा एक्सेस कर सकेगा।

3. सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे ली कुआन ने आसियान के मंच पर ही कहा था कि अगर आसियान को ऊंचाइयों को छूना है तो उसे अपने दोनों पंखों यानी भारत और चीन को शामिल करना ही होगा। यानी सिंगापुर के जरिए भारत आसियान में अच्छी पैठ बना सकता है।

- "सिंगापुर के अच्छे संबंधों से भारत को व्यापार में तो फायदा होगा ही, चीन पर निर्यात की निर्भरता कम होगी।"

- "भारत को शांगरी ला डायलॉग में स्पीच देने के लिए बुलाने का मतलब है कि भारत सरकार और लोगों की कोशिशों से देश का कद जरूर बढ़ा है और मोदी भारत के बढ़ते कद का प्रतिनिधित्व करते हैं।"

दौरे का क्या असर होगा?

- "अगर दक्षिण एशिया को देखें तो भारत केंद्र में दिखाई देता है। भारत तब और बड़ी ताकत बन सकता है जब पड़ोसी देशों को अपने साथ ले आए। ये देश हमारे निकट आने पर सन्निकट पड़ोसी बन जाएंगे। जब हम उनके साथ बेहतर संबंध बना पाएंगे तो वैश्विक शक्ति बनने का रास्ता साफ होगा।"

- "अगर भारत चाहता है कि दुनिया में उसकी बात सुनी जाए तो अपने पड़ोसी देशों के बीच पैठ बनानी होगी।"

- "रूस की नीति है-पिवोट टू एशिया। इसमें रूस चाहता है कि एशिया के देश वॉशिंगटन की बजाय मॉस्को की तरफ देखें। ज्यादातर दक्षिण एशियाई देश चीन से डरे हुए हैं। पहले वे ओबामा में संभावना देखते थे लेकिन ट्रम्प से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में भारत, रूस और बाकी एशियाई देशों के बीच सेतु का काम कर सकता है।"

- "2011 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र को लेकर की गई अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत का क्षेत्र से सीधा संबंध नहीं है लेकिन विश्व की कोई ताकत भारत के बिना वहां अहम रोल अदा नहीं कर सकती।"

पहली बार शांगरी ला डायलॉग में भाषण देंगे मोदी

- विदेश मंत्रालय की सचिव प्रीति सरन के मुताबिक, मोदी 1 जून को सिंगापुर में शांगरी ला डायलॉग में स्पीच देंगे। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को सिंगापुर में संबोधन के लिए बुलाया गया है।

- शांगरी ला डायलॉग 2002 में शुरू हुआ था। इसमें एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और टॉप अफसर शामिल होते हैं।

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार, स्थायी समाधान की रणनीति बना रहे हैं: पेट्रोलियम मंत्री

पेट्रोल-डीजल में लगातार 15वें दिन इजाफा हुआ है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे बढ़कर 78.27 और डीजल 11 पैसे बढ़कर 69.17 हो गया है। मुंबई में रेट बढ़कर 86.06 और 73.64 रुपए हो गए हैं। 14 मई से लगातार कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इस दौरान सरकार ना तो दाम घटाने का फॉर्मूला तलाश पाई है ना ही तेल पर लगाम लग पा रही है। कीमतें हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं। बता दें कि क्रूड में पांच दिन में 5 डॉलर/बैरल कम हुआ है इसके बाद भी दाम नहीं घटे हैं।

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार: पेट्रोलियम मंत्री

इस बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर दोहराया है कि पेट्रोल डीजल पर लगाम लगाने के लिए स्थायी समाधान के लिए लंबी अवधि की रणनीति बनाई जा रही है। पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना भी इन उपायों में शामिल है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के सवाल पर जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम बढ़ने, रुपए में उतार-चढ़ाव और टैक्स की वजह से पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है।

31 मई को विभिन्न समाज के दम्पत्तियों द्वारा नर्मदा जल पूजन से समापन

मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कहा है कि जल अभियान सामाजिक समरसता का भी महाअभियान बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने तपती गर्मी में 45 डिग्री गर्मी में पसीना बहाकर जल अभियान में सहयोग प्रदान करने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।

गुजरात में जन अभियान के रूप में चलाए गए सुजलाम सुफलाम जल अभियान का समापन 31 मई को राज्यभर में विभिन्न समाज के दम्पत्तियों द्वारा नर्मदा का पूजन करके किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर विशेष तौर से तैयार कमांड कंट्रोल वॉल के मार्फत आज श्री विजय रूपाणी ने महेसाणा जिले की विसनगर तहसील के कुंवासणा गांव के नागरिकों, अमरेली जिले की लीलिया तहसील के मोटा लीलिया, पंचमहाल जिले के हालोल, आणंद जिले के चिखोदरा, सुरेन्द्रनगर जिले की वढवाण तहसील के कोठारिया, बनासकांठा की डीसा तहसील के पेछडाल के ग्रामीणों, भरूच के पारखेत गांव के सरपंच और ग्रामीणों के साथ वीडियो कांफ्रेंस से बातचीत कर सुजलाम सुफलाम जल अभियान के कामकाज की समीक्षा की और ग्रामीणों के प्रतिभाव भी जाने।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के संतोष और ग्रामीणों द्वारा व्यक्त की गई हर्ष की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रतिबद्धता जतायी कि राज्य सरकार आगामी तीन वर्ष तक सुजलाम सुफलाम जल अभियान को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून बेहतर रहेगा। जिन जिलों में काम चल रहा है उसे तेजी से पूर्ण करने का उन्होंने निर्देश दिया।

वीडियो कांफ्रेंस के दौरान ग्रामीणों ने इस जल अभियान के अंतर्गत हुए कार्यों से काफी संतोष होने की भावना व्यक्त की और इस अभियान को जारी रखने का आग्रह किया। जलाशयों की मिट्टी किसानों को खेतों के लिए दी जा रही है इस पर किसानों ने प्रसन्नता जतायी।

इस पर प्रतिभाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र नर्मदा के पानी पर ही आधारित रहने के स्थान पर बरसाती जल का अधिकाधिक संग्रह करने के प्रयास किए जाने चाहिये। जल अभियान से जलाशय, तालाब, चेकडेम भरे रहेंगे तो पानी का तल ऊपर आएगा। मानसून आने से पूर्व हमें यह सभी कार्य पूर्ण करने हैं।

बनासकांठा के पेछडाल गांव के नागरिकों ने आनन्द की अभिव्यक्ति में कहा कि राज्य सरकार का यह कार्य भगीरथी कार्य है।

मुख्यमंत्री ने गत मानसून में बाढ़ के समय बनासकांठा जिले में एक सप्ताह तक किए गए कार्यों का स्मरण करते हुए कहा कि राज्य सरकार के ऐसे कार्यों से किसान बहुत खुश हैं। आने वाले दिन और बेहतर होंगे ऐसा शुभ संकेत देकर उन्होंने अग्रिम आयोजन की प्रशंसा की।

7 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंचों और ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंस से बातचीत के इस मौके पर स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, नगरपालिकाओं के पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि, विधायक, सांसद और अग्रणी बड़ी संख्या में मौजूद थे। गांधीनगर में मुख्यमंत्री के अग्र सचिव श्री एम.के. दास, सचिव श्री अश्विनी कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मालिक - मुद्रक -प्रकाशक-संपादक : रेशमा भागवाणी ने लता ग्राफिक्स-२०, सर्जन बंग्लोझ, पार्श्वनाथ टाउनशीप, केनाल के पास, कृष्णनगर, अहमदाबाद से प्रिन्टींग कर के २०, सर्जन बंग्लोझ, पार्श्वनाथ टाउनशीप, केनाल के पास, कृष्णनगर, अहमदाबाद-३८२३४६ से प्रकाशित किया